सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया कलकत्ता HC का फैसला

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई को रेगुलर रूप से जांच अपने हाथ में लेने का आदेश देने से न केवल जांच एजेंसी पर 'बिना वजह बोझ' पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों को भी 'मनोबल गिराने वाले बहुत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव' का सामना करना पड़ता है.

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार महिला को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने संबंधी मामले की एसआईटी जांच का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की.

पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के छह नवंबर के आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था. उसने कहा, "हमारे लिए उन कारणों पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, सिवाय यह कहने के कि मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने से न केवल देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर अकल्पनीय बोझ पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों को भी मनोबल गिराने वाले बहुत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव का सामना करना पड़ता है."

पीठ ने इस आधार पर आगे बढ़ना उचित नहीं समझा कि पश्चिम बंगाल कैडर को आवंटित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच करने और सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ या अक्षम थे. शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी आकाश मघरिया (डीआईजी प्रेसीडेंसी रेंज), स्वाति भंगालिया (एसपी हावड़ा ग्रामीण) और सुजाता कुमारी वीणापानी (हावड़ा की डीएसपी यातायात) शामिल हैं.पीठ ने आदेश दिया, "एसआईटी जांच तत्काल अपने हाथ में लेगी... जांच के सभी रिकॉर्ड आज ही एसआईटी को सौंप दिए जाएंगे और एसआईटी बिना किसी देरी के जांच शुरू कर देगी. अगर आवश्यक हुआ तो एसआईटी कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भी शामिल करने के लिए स्वतंत्र होगी." सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से एक विशेष पीठ गठित करने का आग्रह किया, जिसके समक्ष एसआईटी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करेगी और आगे की जांच के लिए अनुमति मांगेगी.याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिकवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने अपने मुवक्किलों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक लड़की के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत कड़े प्रावधान लागू किए हैं. पीठ ने पीड़ितों को एसआईटी से संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके जीवन और अधिकारों को कोई नुकसान न हो. उसने जांच दल से बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाने को कहा.

पीठ ने कहा, "हमें इन युवा आईपीएस अधिकारियों पर बहुत भरोसा है... संवैधानिक लोकाचार के संदर्भ में इन अधिकारियों पर लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हमें उम्मीद है कि वे इन बातों को समझेंगे." हुड्डा ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी "मामले में खरे उतरेंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट के आठ अक्टूबर के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने का आदेश दिया गया था

हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों को कैसे मात दी

राज्य में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तक़रीबन अकेले दम पर बीजेपी के तमाम दिग्गज़ों को मात दी है.

यह एकमात्र राज्य रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी ख़बर आई है.

झारखंड में बीजेपी की तरफ से ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे नेताओं ने प्रचार किया था.

झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन की जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, जबकि उनके गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं.

इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राज्य की 14 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं.

लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी के खाते में भी एक सीट आई थी.

सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनावों के छह महीने के बाद हुए चुनावों में हेमंत सोरेन को इतनी बड़ी कामयाबी कैसी मिली और वो किस तरह से बीजेपी को बड़ी मात दे पाने में सफल हुए?

इसी साल जून में जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में ख़ुद के जेल जाने को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया था.

झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार बिनय कुमार कहते हैं, ₹हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया है कि वो ही आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं. उन्होंने झारखंड में आदिवासी-मूलवासी का मुद्दा उठाया और ख़ुद को धरतीपुत्र बताया, जिसमें वो सफल रहे.₹

बिनय कुमार का मानना है, ₹हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रहे कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो राज्य का शासन दिल्ली से चलेगा. झारखंड के आदिवासी स्वभाव से ही विद्रोही होते हैं, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि राज्य का शासन दिल्ली से चले.₹

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी वोटरों का दबदबा है. इन सीटों पर तीन दशक से भी ज़्यादा समय से जेएमएम का वर्चस्व रहा है.

साल 2019 के पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो इन 28 में से महज़ दो सीट पर ही बीजेपी की जीत हुई थी और इस बार वहां भी बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती नहीं दे पाई है.

बीजेपी ने झारखंड में आदिवासियों को रिझाने की पूरी कोशिश की. उसने जेएमएम के पुराने नेता चंपई सोरेन को भी अपने पाले में खींच लिया, लेकिन फिर भी आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं दे पाया.

हेमंत सोरेन की इस जीत में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है.

राज्य की हेमंत सरकार 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना' चलाती है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते हैं.

इस योजना की घोषणा चुनाव के क़रीब 3 महीने पहले की गई. इसके तहत 16 लाख़ महिलाओं के खाते में पैसे भी आने शुरू हो गए.

हेमंत सोरेन ने चुनावों के ठीक पहले इसे ढाई हज़ार करने का वादा किया, जिसका असर वहां दिखाई दिया.

वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन कहते हैं, ₹झारखंड की 81 सीटों में 31 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के वोटिंग प्रतिशत से ज़्यादा रहा है और इसका फ़ायदा जेएमएम और उसके सहयोगी दलों को मिला है.

झारखंड में जेएमएम की जीत और हेमंत सोरेन को मिली सफलता में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है.

फ़ौजी परिवार से ताल्लुक रखने वाली कल्पना सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी सोच बहुत व्यापक है. वो अंग्रेज़ी, हिन्दी, संताली और उड़िया ज़ुबान जानती हैं.

कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनावों के दौरान क़रीब 100 सभाएं की और उनकी सभाओं में लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई.

बिनय कुमार कहते हैं, ₹कल्पना सोरेन ने हेमंत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है. हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पहली बार वो सियासत के मैदान में उतरी थीं और पहली बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया.₹

हेमंत सोरेन को इसी साल जनवरी महीने में ईडी ने गिरफ़्तार किया था. गिरफ़्तारी के क़रीब 5 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन को ज़मानत दी थी.

इस दौरान हेमंत सोरेन ने जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी दी थी. हालाँकि जेल से बाहर आने के बाद हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बन गए और चंपई सोरेन ने इसे अपमान बताकर पार्टी छोड़ दी.

हेमंत सोरेन ने ख़ुद के जेल जाने को भी अस्मिता से जोड़ा और जेल से बाहर आने के बाद कहा, ₹आज मैं फिर अपने राज्य की जनता के बीच हूं.₹

₹जो संकल्प हमने लिया है उसे हम मकाम तक ले जाने का काम करेंगे. आज मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, किस तरह से हमारे ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचा गया.₹

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत देते हुए कहा था, ₹किसी भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त ज़मीन के अधिग्रहण और कब्ज़े में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई ज़िक्र नहीं है.₹

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण हैं कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है.

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं. वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं.

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया.

आनंद मोहन बताते हैं, ₹जेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को जोड़ने में सफल रही हैं. बीजेपी झारखंड में अपना वोट बढ़ाने में नाकाम रही है और इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिला है.

आनंद मोहन कहते हैं, ₹बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन यह काम में नहीं आया. दूसरा राज्य में उसके सहयोगी दलों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे हेमंत सोरेन और जेएमएम को मदद मिली है.₹

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी. जबकि जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को महज़ एक सीट मिली थी.

इसके अलावा सीपीआई(एमएल) को उन चुनावों में एक सीट, आजसू पार्टी को 2 सीट और बाबूलाल मरांडी की जेवीएम को 3 सीटें मिली थीं.

जेवीएम के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी इस बार बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है, जबकि जेएमएम और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन इस बार बेहतर हुआ है.

माना जाता है कि हेमंत सोरेन की जीत में महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना', सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का वादा अहम रहा है.

इसके अलावा राज्य में 200 यूनिट मुफ़्त बिजली और पुराने बिजली के बकाया बिल की माफ़ी ने भी हेमंत को मिली जीत में योगदान दिया है.

यह भी माना जाता है कि बीजेपी के पास हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाला कोई चेहरा नहीं था.

बिनय कुमार कहते हैं, ₹बीजेपी जो भी नैरेटिव सेट करना चाह रही थी वो यहां के जनमानस के अनुकूल नहीं था, उसे यहाँ के नेताओं को आगे करना था. बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या रघुवर दास जैसे नेताओं को आगे करने से परिणाम कुछ अलग होते.₹

जबकि इसके विपरीत माना जाता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड और यहां के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया.

झारखंड में महिलाओं की चुनावों में भागीदारी को हेमंत सोरेन को मिली कामयाबी से जोड़कर देखा जाता है

गौतम अदानी से क्या है नाता?

भारत का चर्चित अदानी ग्रुप का नाम एक बार फिर विवादों में घिर गया है.

कंपनी के संस्थापक गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी समेत आठ लोगों के ख़िलाफ़ अमेरिका में धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए गए हैं.

गौतम अदानी और इन सात लोगों पर आरोप हैं कि उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीएल) के लिए ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2,100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साज़िश रची थी.

साथ ही उन्होंने ये जानकारियाँ छिपाकर अमेरिकी वित्तीय बाज़ार से दो अरब डॉलर जुटाए थे. उन पर धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है.

कंपनी पर लगे आरोप क्या हैं?

सागर अदानी अपने करियर की शुरुआत से ही अदानी ग्रीन्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं. सागर को अदानी समूह और परिवार में 'नई पीढ़ी' के रूप में देखा जाता है.

इसके अलावा विनीत जैन भी लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं. वो एजीएल में सीईओ थे और वर्तमान में प्रबंध निदेशक के पद पर हैं.

अमेरिका में हुई कार्रवाई के बाद अदानी समूह के शेयर की क़ीमतों में भी भारी गिरावट आई है.

एजीईएल ने डॉलर-मूल्य वाले बांड के माध्यम से 60 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना को स्थगित कर दिया है.

वहीं कंपनी ने अपने निदेशकों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को 'आधारहीन' बताया है.

ग़ौरतलब है कि इससे पहले जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके कारण अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की क़ीमतें गिर गईं थी.

बुधवार को गौतम अदानी और अन्य के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया.

उन पर भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर (लगभग दो हजार 100 करोड़ रुपए) की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

इसके चलते कंपनी को अगले 20 सालों में दो अरब डॉलर (मौजूदा क़ीमत पर 169 अरब रुपए) का फ़ायदा होने का अनुमान था.

अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, गौतम अदानी ने ख़ुद भारतीय अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और रिश्वत पर चर्चा की.

इसके अलावा कंपनी के आंतरिक ईमेल्स में कोडवर्ड में गौतम अदानी के नाम की चर्चा थी. अभियोग (पेज 20) के अनुसार, गौतम अदानी को 'एसएजी', 'न्यूमरो यूनो', 'द बिग मैन' जैसे कोडवर्ड से संबोधित किया जाता था.

आरोप पत्र के मुताबिक़, अप्रैल 2022 में अहमदाबाद में अदानी ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफ़िस में गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन और अन्य लोगों के बीच बातचीत हुई थी.

गौतम अदानी की गिनती भारत के शीर्ष उद्योगपतियों में होती है.

फ़ोर्ब्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़ गौतम अदानी की कुल संपत्ति में लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट आई है. वो दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों की सूची में 25वें स्थान पर हैं.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले वे टॉप 10 में पहुँच गए थे.

सागर अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं. वो गौतम अदानी के भाई राजेश के बेटे हैं.

कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक़ सागर ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है.

सागर 2015 से अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो शुरुआत से ही एजीईएल से जुड़े हुए हैं.

अदानी ग्रीन एनर्जी की सभी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का क्रेडिट सागर को ही दिया जाता है.

वो कंपनी के रणनीतिक और वित्तीय मामलों को संभालते हैं और विदेश में भी ग्रुप का काम करते हैं.

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (साल 2023-24) के अनुसार सागर सतत ऊर्जा (रिन्यूएबेल एनर्जी) के अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अदानी समूह के प्रयासों का नेतृत्व करते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार सागर के पास व्यवसाय, रिस्क मैनेजमेंट, वित्त, वैश्विक अनुभव, विलय और अधिग्रहण, तकनीकी अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और कॉरपोरेट प्रशासन में विशेषज्ञता है.ट्रेंडलाइन, भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों और उनके निदेशकों के बारे में जानकारियाँ जुटाता है. उसके मुताबिक़ सागर अदानी 2019 में अदानी ग्रीन एनर्जी में एक कार्यकारी निदेशक थे.

उस समय उन्हें रुपए में वार्षिक वेतन मिलता था. उस समय ये राशि 50 लाख रुपए थी.

साल 2020 में ये आंकड़ा एक करोड़ से ऊपर पहुँच गया था और साल 2022 में ये आंकड़ा तीन करोड़ से ऊपर पहुँच गया था.

ट्रेंडलाइन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सागर को चार करोड़ रुपए का वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें भत्ते के रूप में 40 लाख रुपए अलग से मिलते हैं.

कार्यकारी निदेशक के रूप में सागर का पाँच साल का कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में ख़त्म हो गया था. बाद में उन्हें अगले पाँच साल के लिए फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था.

आरोप पत्र के अनुसार मार्च 2023 में जब सागर अदानी अमेरिका में थे, तो अमेरिकी जांच एजेंसी, एफ़बीआई ने उनके ख़िलाफ़ सर्च वारंट जारी किया. सागर के पास से एफ़बीआई ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किया.

जाँच में सामने आए विवरण के अनुसार सागर को इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए यह जानकारी मिलती थी कि किस अधिकारी को कुल कितनी रिश्वत देनी है, प्रत्येक राज्य (या केंद्रशासित प्रदेश) रिश्वत के लिए लगभग कितनी बिजली ख़रीदेगा.

आरोप ये भी है कि सरकारी अधिकारियों के नाम संक्षिप्त कर दिए गए थे और कुछ मामलों में प्रति मेगावाट रिश्वत तय की गई थी.

सागर पर निवेशकों को गुमराह करने, तथ्यों को छिपाने और निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है.

सागर सहित अन्य लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक चैट, दस्तावेज़ और प्रेज़ेन्टेशन्स को नष्ट कर क़ानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप है.

इंडिया फाइलिंग्स कंपनी के निदेशकों और कंपनियों के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी जुटाती है.

इसके मुताबिक सागर अदानी, अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, अदानी फ़िनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, अदानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, अदानी हाउसिंग फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी थ्री लिमिटेड और अदानी हेल्थ वेंचर्स से जुड़े हुए हैं.

इसके अलावा वो अदानी वेंचर्स, अदानी रिन्यूएबल पावर, अदानी ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में भी बतौर निदेशक काम करते हैं.

अमेरिका में न्याय मंत्रालय की ओर से दायर अभियोग के अनुसार भ्रष्टाचार 2020 और 2024 के बीच हुआ.

54 पन्नों के इस अभियोग पत्र में अदानी के अलावा विनीत जैन का भी बार-बार ज़िक्र है.एजीईएल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक़ विनीत जैन अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं.

विनीत 15 साल से अधिक समय से अदानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं. मई 2023 में कंपनी के एमडी बनने से पहले विनीत ने कंपनी में सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) की भूमिका भी निभाई थी.

विनीत, अदानी समूह की ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा से जुड़ी परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हैं.

रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली उत्पादन, पावर ट्रांसमिशन और बिजली वितरण क्षेत्रों में उनकी गहरी समझ मानी जाती है.

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार अदानी समूह ने तमिलनाडु के कामुदी में एक सौर परियोजना शुरू की है. इस परियोजना को शुरू करने में विनीत जैन की अहम भूमिका मानी जाती है.

इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने देश की पहली और सबसे लंबी प्राइवेट हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन बिछाने में अहम भूमिका निभाई थी.

अदानी समूह का दावा है कि वह देश में सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट पर काम कर रहा है. इसमें भी विनीत जैन की महत्वपूर्ण भूमिका है.

आरोप के मुताबिक़ अप्रैल-2022 में गौतम अदानी और अन्य लोगों के बीच नई दिल्ली में रिश्वत की रकम को लेकर मीटिंग होनी थी.

इससे पहले विनीत जैन ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक तस्वीर भेजी थी, जिसमें विदेशी निवेशक अपने हिस्से के रुपए का भुगतान करता है.

इसमें ये आश्वासन दिया गया था कि अगर विदेशी निवेशक अपने हिस्से के 55 करोड़ रूपए की रिश्वत दे तो 650 मेगावॉट की बिजली खरीद समझौता दिया जाएगा.

इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया था कि 583 करोड़ के बदले 2.3 गीगावॉट बिजली ख़रीद समझौता किया जाएगा.

अदानी ग्रीन एनर्जी की स्थापना अदानी एंटरप्राइजेज की एक इकाई के रूप में की गई थी. एजीईएल को जून 2018 में लिस्ट किया गया था.

उस समय प्रति शेयर 10 रुपए की क़ीमत पर एक अरब 58 करोड़ से ज़्यादा शेयर जारी किए गए.

कंपनी का कहना है कि वह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर और पवन संचालित परियोजनाएं संचालित करती है. इसके अलावा सोलर पार्क का भी प्रबंधन करती है.

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक़ उसका लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना है.

वर्तमान में कंपनी 11 हज़ार 184 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करती है.

इसमें से सात हज़ार 400 मेगावाट सौर, एक हज़ार 650 मेगावाट पवन और दो हज़ार 140 मेगावाट (हाइब्रिड) उर्जा का उत्पादन होता है.कंपनी राजस्थान में एक सोलर पार्क संचालित करती है.

इसके अलावा कंपनी ने गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में बंजर भूमि पर 30 मेगावाट के रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र की एक परियोजना शुरू की है.

कंपनी का दावा है कि यह दुनिया में सबसे बड़ा रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र होगा.

एजीईएल ने 600 मिलियन डॉलर मूल्य के बांड जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद उसने अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं.

इसे पहले भी इस प्रोजेक्ट को एक बार स्थगित किया जा चुका है.

कंपनी ने अमेरिकी न्याय मंत्रालय और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह इस मामले में हर संभव क़ानूनी उपाय करेगी.

अदानी समूह का कहना है कि वह प्रबंधन के उच्चतम सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी जहां भी काम करती है वहां क़ानूनों का पालन करती है और पारदर्शिता बनाए रखती है.